



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2009/आषाढ़ 19, 1931

No. 238]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2009/ASADHA 19, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2009

**विषय :** चीन जन. गण. से कॉमेरिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/17/2009-डीजीएडी.—यतः मै. एटलस फाइन कैमिल्स प्रा. लि., नासिक रोड, महाराष्ट्र-422101, घरेलू उत्पादक ने 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने चीन जन. गण. (जिन्हें एतद्वारा संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अधका वहाँ से निर्यातित कॉमेरिन (जिसे एतद्वारा संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के कथित पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है और ऐसे पाटित संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि सम्बद्ध देश की सम्बद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं इसलिए प्राधिकारी कथित पाटन की मात्रा और प्रभाव को

निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने, जिसकी यदि वसूली की जाती है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार उक्त कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की एतद्वारा जांच प्रारम्भ करते हैं।

**क. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार का कॉमेरिन (जिसे एतद्पश्चात् “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) है। कॉमेरिन (रासायनिक सूत्र— $C_6H_{10}O_2$ ) रसायन के लेक्टोन परिवार में आता है। यह एक सुगंधित रसायन है जो सफेद दानों, फ्लेक या पाउडर के रूप में हो सकता है। इसकी विशेष ताजे कटे हुए चारे जैसी और खट्टी सुगंध वैनीला से मिलती-जुलती है। कॉमेरिन का प्रयोग सुगंधित यौगिकों के निर्माण में किया जाता है और उन सुगंधित यौगिकों का प्रयोग साबुन, डिटॉन, शृंगार सामग्री, अगरबत्ती तथा परिष्कृत सुगंधियों के निर्माण में किया जाता है। इसकी महक सुगंधित होती है और कई अन्य घरेलू एवं औद्योगिक उत्पादों में मौजूद दुग्धीय को ढक लेती है। कॉमेरिन जो कि मूल रूप से टॉका बीन्स से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक उत्पाद था, अब इसका उत्पादन कृत्रिम रूप से किया जाता है। इसे दो कृत्रिम प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् (i) सैलिसलिडहाइड प्राप्त करने के लिए फिनॉल से शुरू करके तत्पश्चात् पर्किन्स प्रतिक्रिया और (ii) ऑर्थो-क्रेसोल जिसे रैशिंग पद्धति भी कहा जाता है जिसमें ऑर्थो-क्रेसोल से सैलिसलिडहाइड बनाया जाता है और उसे कॉमेरिन में परिवर्तित किया जाता है, से शुरुआत। दोनों प्रक्रियाओं में सैलिसलिडहाइड एवं एसिटिक एन्हाइड्राइड दोनों उत्प्रेरक के रूप में एसिटिक एसिड में सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं और आसवन के द्वारा अपरिष्कृत कॉमेरिन को एसिटिक एसिड से अलग किया जाता है। कई बार आसवन के द्वारा

अपरिष्कृत कॉमेरिन का शुद्धिकरण किया जाता है और फिर उसे मैन्थॉल में रवाकृत किया जाता है। अभिकेन्द्रन के द्वारा खाकृत उत्पाद को अलग किया जाता है और सुखाया जाता है। कॉमेरिन तथा मुख्य भौतिक विनिर्देशन उसकी शुद्धता होती है जिसके लिए उसका द्रवणांक संकेतक होता है। किसी भी एकल उत्पाद या उत्पादों के संयोजन के द्वारा कॉमेरिन को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

4. इस उत्पाद का दायरा सीमा-शुल्क उपर्योग सं. 2932.21.00 के अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 (कार्बनिक रसायन) के तहत वर्गीकृत है।

5. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं विशेषताओं के संदर्भ में जैसे कि भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं से तुलनीय है और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं है तथा दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान माना जा रहा है।

#### ख. घरेलू उद्योग तथा उसका मत

6. यह याचिका मै. एटलस फाइन कैमिकल्स प्रा. लि., नासिक रोड, महाराष्ट्र-422101 द्वारा दायर की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि वे संबद्ध वस्तु के एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं और मामले से संबंधित सूचना प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता का मत है कि भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक थे। हालांकि उन दोनों ने अब अपना वाणिज्यिक उत्पादन बंद कर दिया है और तदनुसार, प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा शत-प्रतिशत बनता है।

7. प्राधिकारी ने उपर्युक्त की जांच के पश्चात् यह निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग है और याचिकाकर्ता उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के संदर्भ में सभी मानदण्डों को पूरा करता है।

#### ग. शामिल देश

8. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य (जिसे चीन जन.गण. भी कहा गया है) है।

#### घ. सामान्य मूल्य

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियम के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सूचित किया है कि वे चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सके और इसलिए चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि संबद्ध वस्तु कॉमेरिन का उत्पादन पूरे विश्व में केवल भारत, चीन, जन. गण. तथा फ्रांस में ही होता है और इसलिए बाजार-अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का विकल्प अत्यंत सीमित है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए फ्रांस को समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जाए और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए फ्रांस से भारत में लाभकारी बिक्री कीमत तथा भारत से फ्रांस में लाभकारी बिक्री कीमत पर विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का यह भी अनुरोध है कि वे इस चरण में फ्रांस में संबद्ध वस्तु की कीमत से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं कर सके।

10. पाटनरोधी नियम के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए सामान्य मूल्य से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। तथापि, नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु एक समुचित सदृश देश के संबंध में सुझाव देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा आमंत्रित किया जाता है।

#### ङ. निर्यात कीमत

11. याचिकाकर्ता ने सूचित किया है कि मांग के निर्धारण हेतु ध्यान में रखे गए आयात आईबीआईएस आंकड़ों पर आधारित हैं और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के स्थान पर आईबीआईएस आंकड़ों का प्रयोग करने से पहले उन्होंने दोनों स्रोतों से प्राप्त आयात की मात्रा संबंधी आंकड़ों का मिलान चीन जन. गण. से भारत को किए गए नियात के संबंध में चीन के सीमा-शुल्क विभाग द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के साथ किया है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित जांच अवधि में आईबीआईएस (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना प्रणाली) द्वारा प्रदत्त सौदे-वाद आयात आंकड़ों के आधार पर भारित औसत आयात कीमत के रूप में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की नियात कीमत का निर्धारण किया है। कारखाना द्वारा नियात कीमत के निर्धारण के लिए नियात के देश में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन संबंधी व्यय, बैंक प्रभार तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजन के दावे किए गए हैं।

12. पाटनरोधी नियम के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए नियात कीमत के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

#### च. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य तथा नियात कीमत की तुलना कारखाना द्वारा स्तर पर की गई है जिसे संबद्ध देश के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। जांच को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है कि संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना द्वारा नियात कीमत की तुलना से काफी अधिक है तथा संबद्ध देश से नियातक (नियातकों) उत्पादक (उत्पादकों) द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

#### छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

14. याचिकाकर्ता ने वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न मानदण्डों के विषय में सूचना उपलब्ध कराई है। यद्यपि संबद्ध वस्तुओं

की मांग में काफी वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग इसके बावजूद भी लगातार पाटन के कारण अपनी मौजूदा क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं। अतः निरंतर पाटन के कारण उनकी क्षमताओं की उपयोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन को क्षति पहुंची है। आयातित एवं घरेलू उत्पाद के बीच अत्यधिक कीमत अंतर से घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री मात्रा में वृद्धि करने में बाधा आ रही है। आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है। इसके परिणामस्वरूप पाटन से कीमत में वृद्धि करने में रुकावट आ रही है, जिसमें अन्यथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण वृद्धि हो गई होती। लगातार पाटन से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है जिससे लगाई गई पूंजी तथा नकद लाभों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। पाटन से घरेलू उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग को प्रथमदृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण समग्र एवं संचयी रूप से क्षति पहुंची है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मूल्य एवं मात्रा, लाप, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, वस्तु सूचियों तथा बाजार हिस्से के संदर्भ में गिरावट आई है तथा अत्यधिक मांग की मौजूदगी के बावजूद घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग ईस्टम से कम रहा है।

15. पाटनरोधी नियमों से संदर्भ में पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कारणात्मक संबंध के विषय में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

#### ज. जांच की अवधि ( पीओआई )

16. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक की है। तथापि क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

#### झ. सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादक (उत्पादकों)/निर्यातक (निर्यातकों) तथा भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारें, भारत में संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं उपयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
वाणिज्य विभाग,  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी),  
कमरा सं.-240, उद्योग भवन,  
नई दिल्ली-110011

18. कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समय-सीमा में निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

#### अ. समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

#### ठ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. पाटनरोधी नियम के नियम 7 के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीयता का दावा करने के कारणों के साथ प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपांतर अथवा अगोपनीय सारांश प्रयोगितः विस्तृत होना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना का अर्थ स्पष्ट हो सके। यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विचार से सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता, तो उसके कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

#### ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं।

#### ड. उपलब्ध तथ्यों का उपयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND  
ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2009

**Subject:** Initiation of anti-dumping investigations concerning imports of Coumarin originating in or exported from China PR.

No.14/17/2009-DGAD.—Whereas M/s. Atlas Fine Chemicals Pvt. Limited, Nasik Road, Maharashtra-422101, the domestic producer has filed a Petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975

as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), alleging dumping of Coumarin (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and have requested for initiation of anti-dumping investigations against the imports of the subject goods from the subject country and levy of anti-dumping duty on such dumped subject goods.

2. And whereas, the Authority finds that sufficient *prima facie* evidence of dumping of subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### A. Product under consideration and Like Article

3. The product under consideration in the present investigation is Coumarin of all types (hereinafter referred as "subject goods"). Coumarin (Chemical Formulae  $C_9H_6O_2$ ) is in the lactone family of chemicals. It is an aroma chemical, which can be in the form of white crystals, flake or powder. It has characteristic odour of newly mown hay and bittersweet somewhat similar to vanilla. Coumarin is used in the preparation of fragrance compounds and those fragrance compounds are used in the production of soaps, detergents, cosmetics, incense sticks and fine fragrances. It imparts pleasant fragrance and masks unpleasant odours in many other household and industrial products. Coumarin, which was originally a natural product obtained from Tonka beans is now produced synthetically. It can be obtained by two synthetic processes i.e. (i) starting from phenol to obtain Salicylaldehyde followed by Perkin reaction and (ii) starting from Ortho-cresol which is also called Raschig method in which Salicylaldehyde is made from Ortho-cresol and then converted into Coumarin. In both the processes Salicylaldehyde and Acetic Anhydride react in the presence of Sodium Acetate in Acetic Acid as catalyst and crude Coumarin is separated from Acetic Acid by distillation. The crude Coumarin is further purified by several distillations and then crystallized in Menthol. The crystallized product is separated by centrifugation and dried. The main physical specification of Coumarin is its purity, for which the melting point is the indicator. There is no replacement for Coumarin by any single product or combination of products.

4. The scope of the product is classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act under Customs Sub-heading No. 2932.21.00.

5. The petitioner has claimed that there is no known difference in petitioner's product and subject goods exported from the subject country and are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods and there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from the subject country and the both are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present investigations, the goods produced by the domestic industry are being treated as like article to the subject goods imported from the subject country in accordance with the AD Rules.

#### B. Domestic Industry and Standing

6. The petition has been filed by M/s. Atlas Fine Chemicals Pvt. Limited, Nasik Road, Maharashtra-422101 claiming that they are the sole domestic producer of the subject goods and has provided relevant information. The petitioner has stated that there were two other producers of the subject goods in India, however, both of them have closed their commercial production and, accordingly, the petitioner has accounted for 100% of the Indian production during the proposed Period of Investigation.

7. The Authority, after examining the above, determines that the petitioner constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) read with Rule 2(d) of the Anti Dumping Rules and the petitioner satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

#### C. Countries involved

8. The country involved in the present investigation is the People's Republic of China (also referred to as China PR.).

#### D. Normal Value

9. The petitioner has claimed that China PR should be treated as non-market economy and, therefore, the Normal Value should be determined in accordance with Paras 7 and 8 of Annexure-I of the AD Rules. The petitioner has stated that they could not get any information about the Normal Value in China PR and, accordingly, the Normal Value has been constructed considering China PR as a non-market economy country. The petitioner has stated that Coumarin, the subject goods are produced only in India, China PR and France around the world and, accordingly, the choice of market economy third country is extremely limited. The Petitioner has submitted that France can be considered as an appropriate market economy third country for the determination of Normal Value and profitable selling price from France to India or profitable selling price from India to France can be considered for determination of Normal Value. The petitioner has also submitted that they were not able to get price of subject goods in France at this stage.

10. There is sufficient evidence with regard to Normal Value to justify initiation of Anti dumping Investigations in terms of the AD Rules. However, in accordance with Para 7 to Annexure-I of the Rules, interested parties are hereby invited to suggest an appropriate analogue country for determination of Normal Value in China PR within the specific time limit laid down in this notification.

#### E. Export Price

11. The petitioner has stated that the imports considered for assessment of demand are based upon IBIS Data and before adopting IBIS Data instead of DGCI&S Data they have correlated the import volumes from both the sources with the data reported by Chinese Customs for exports from China PR to India. The petitioner has claimed export price of the subject goods from the subject country as the weighted average import price in the proposed Period of Investigation, based on transaction wise import data provided by the IBIS (International Business Information System). Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port expenses, bank charges and credit cost in the country of exports to arrive at ex-factory export price.

12. There is sufficient evidence with regard to Export Price to justify initiation of anti dumping investigations in terms of the AD Rules.

#### F. Dumping Margin

13. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of subject country. There is sufficient prima facie evidence to justify investigations that the normal value of the subject goods is significantly higher than the ex-factory export price and that the subject goods are being dumped by exporter(s)/producer(s) from the subject country.

#### G. Injury and Casual Link

14. The petitioner has furnished information on various parameters relating to material injury. Though, the demand of the subject goods has grown up significantly the domestic industry even after that is unable to utilize their existing capacities due to continuous dumping. Continuous dumping has therefore adversely affected its utilization of capacities. Resultantly, production has suffered. Significant price difference between imported and domestic product is preventing the domestic industry from increasing its sales volumes. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Consequently, dumping is preventing price increases that would have otherwise occurred as a result of increase in the cost of production. Persistent dumping has adversely affected profitability of the domestic industry. The domestic industry has suffered financial losses during the injury period and that has directly impacted upon the return on capital employed and cash profits. Dumping has adversely affected the growth of the domestic industry. Prima facie,

the domestic industry has suffered collectively and cumulatively material injury on account of dumping of subject goods from subject country. The Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales values and volume, profits, return on investments, cash flow, inventories and market share and the capacity utilization of the domestic industry continued to remain sub-optimal in spite of existence of significant demand.

15. There is sufficient evidence with regard to injury to the domestic industry and the causal link, to justify initiation of an anti-dumping investigations in terms of the AD Rules.

#### H. Period of Investigation (POI)

16. The Period of Investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st January, 2008 to 31st December, 2008. The injury investigation period will however, cover the periods 2005-06, 2006-07, 2007-08 and the Period of Investigation.

#### I. Submission of Information

17. The known producer(s)/exporter(s) of the subject country and their Government through their Embassy in India, the known importers and known users in India to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to enable them to submit their relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,  
Ministry of Commerce and  
Industry, Department of Commerce,  
Directorate General of Anti-Dumping  
and Allied Duties (DGAD),  
Room No. 240, Udyog Bhavan,  
New Delhi-110011

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### J. Time Limit

19 Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above mentioned address not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

#### K. Submission of Information on non-confidential Basis

20. In terms of Rule 7 of the AD Rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority along with the reasons for claiming confidentiality. The

non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

**L. Inspection of Public File**

21. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version

of the evidence submitted by other interested parties.

**M. Use of Facts Available**

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority